

MEDIA COVERAGE REPORT



SOHAN LAL COMMODITY MANAGEMENT PVT. LTD

Budget Expectation Quote

INDEX**Print Coverage**

S.No.	Date	Publication	Edition	Headline
1	02-July-2019	The Pioneer	New Delhi/Chandigarh/Ranchi	Agri- warehousing cos seek GST waiver ahead of union budget
2	02-July-2019	National Express	New Delhi	What are the expectations of NBFCs from budget : Sandeep Sabharwal
3	02-July-2019	Vir Arjun	Ahmedabad	Make indirect taxes logical for warehousing sector

Online Coverage

S.No.	Date	Portal	Headline	Link
1	02-July-2019	www.business-standard.com	Agri-warehousing cos seek GST waiver ahead of Union Budget	https://www.business-standard.com/article/pti-stories/agri-warehousing-cos-seek-gst-waiver-ahead-of-union-budget-119070200803_1.html
2	02-July-2019	www.financialexpress.com	Budget 2019: Agri-warehousing companies seek GST waiver ahead of Union Budget	https://www.financialexpress.com/budget/budget-2019-agri-warehousing-companies-seek-gst-waiver-ahead-of-union-budget/1626278/
3	02-July-2019	www.livemint.com	Agri-warehousing companies seek GST waiver ahead of Union Budget	https://www.livemint.com/budget/expectations/agri-warehousing-companies-seek-gst-waiver-ahead-of-union-budget-1562067670089.html
4	02-July-2019	www.newindianexpress.com	Agri-warehousing companies seek GST waiver ahead of Union Budget	http://www.newindianexpress.com/business/2019/jul/02/agri-warehousing-companies-seek-gst-waiver-ahead-of-union-budget-1998426.html
5	03-July-2019	www.newsnation.in	Agri-warehousing companies seek GST waiver ahead of Union Budget	https://www.newsnation.in/business-news/budget-2019/agri-warehousing-companies-seek-gst-waiver-ahead-of-union-budget-article-229445.html
6	02-July-2019	www.theweek.in	BIZ-AGRI WAREHOUSING	https://www.theweek.in/wire-updates/business/2019/07/02/

				ccm1-biz-agri%20warehousing.html
7	02-July-2019	www.Devdiscourse.com	Agri-warehousing cos seek GST waiver ahead of Union Budget	https://www.devdiscourse.com/article/business/583035-agri-warehousing-cos-seek-gst-waiver-ahead-of-union-budget
8	02-July-2019	www.timesnownews.com	Agri-warehousing companies seek GST waiver ahead of Union Budget	https://www.timesnownews.com/business-economy/budget/article/agri-warehousing-companies-seek-gst-waiver-ahead-of-union-budget/447272
9	03-July-2019	www.dailypioneer.com	Agri-warehousing cos seek GST waiver ahead of Union Budget	https://www.dailypioneer.com/2019/business/agri-warehousing-cos-seek-gst-waiver-ahead-of-union-budget.html
10	02-July-2019	www.commodityonline.com/commodity	What are the expectations of Agri Sector from Modi 2.0 government's first Budget?	https://www.commodityonline.com/commodity-news/what-are-the-expectations-of-agri-sector-from-modi-20-governments-first-budget/news-now/26010
11	01-July-2019	www.indianshowbiz.com	Sohan Lal Commodity Management Pvt. Ltd.	http://www.indianshowbiz.com/?p=188485
12	03-July-2019	www.deccanherald.com	Rationalisation of indirect taxes on warehouse sector	https://www.deccanherald.com/business/budget-2019/rationalisation-of-indirect-taxes-on-warehouse-sector-744484.html
13	03-July-2019	www.india.com	Union Budget 2019: Agri-warehousing Companies Seek GST Waiver to Boost Farming Community	https://www.india.com/business/union-budget-2019-agri-warehousing-companies-seek-gst-waiver-to-boost-farming-community-3706572/
14	03-July-2019	hindi.timesnownews.com	Budget Demand: कृषि भंडारण कंपनियों की बजट में जीएसटी छूट की मांग	https://hindi.timesnownews.com/business/article/agri-logistics-companies-demand-gst-rate-cut-in-budget/447870

Electronic Coverage

S.No.	Date	Publication	Time	Duration
1	26-06-2019	CNBC TV 18	03:50 PM	04:53

Print Coverage

Agri-warehousing cos seek GST waiver ahead of Union Budget

PTI ■ KOLKATA

Days ahead of the Union Budget, agri-warehousing companies have sought waiver of the 18 per cent GST imposed on such services to boost the farming community.

“The Centre should relook at the GST on agri-warehousing services. It is raising the cost of farmers. I think the government should waive the GST on this sector,” said Paran Dass, Transportation Director of Japanese warehousing major Kawasaki Rikuso.

The waiver will encourage farmers to store their produce and prevent distress sale, Dass told *PTI*.

KRT has set up a solar

agri-warehouse in the state, which is used by the West Bengal Agriculture Department.

Sohan Lal Commodity Management Group CEO Sandeep Sabharwal said the GST waiver is a long-standing demand of the agri-warehousing industry.

“The leases of these warehouses are treated as commercial ones, and has an 18 per cent GST implication. On the contrary, output services are devoid of any GST and eventually, the customers’ cost increases,” he said.

This often leads to loss of business for the organised sector, as consumers prefer unorganised players who often do not pay GST, he said.

बजट से क्या उम्मीदें रखती हैं गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियां: संदीप सभरवाल



संदीप सभरवाल

ऐग्री वेअरहाउसिंग इंडस्ट्री बहुत लंबे समय से यह मांग करती आ रही है की अप्रत्यक्ष करों को तर्क संगत बनाया जाए। ऐग्री लॉजिस्टिक्स एवं वेअरहाउसिंग के संगठित क्षेत्र

में काम करने वाली कोई कंपनी जब फसल के लिए ऐग्री इनपुट सेवाएं देती है तो वह वेअरहाउस को लीज पर लेती है और उसमें लॉजिस्टिक्स का उपयोग करती है। इन वेअरहाउसों की लीज को कमर्शियल लीज के तहत रखा जाता है, इस कारण इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। दूसरी तरफ आउटपुट सेवाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगता। इस तरह 18 प्रतिशत जीएसटी से इन कंपनियों को लागत बढ़ जाती है जिसका बोझ ग्राहकों को उठाना पड़ता है।

इस बजट से अक्सर संगठित क्षेत्र को कारोबार की हानि होती है क्योंकि ग्राहक असंगठित क्षेत्र की ओर चले जाते हैं क्योंकि वहां अक्सर जीएसटी नहीं लगाया जाता। पिछले लगातार तीन बजटों से हम यही मांग

करते आ रहे हैं की ऐसी लीज नीति बनाई जाए जिसके अंतर्गत उन कमर्शियल वेअरहाउसिस को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए जिसका इस्तेमाल ऐग्री इनपुट रखने के लिए होता है।

ऐग्री फायनेंस ग्रामीण वित्तपोषण का उपवर्ग है जो छोटीबाड़ी की गतिविधियों को वित्तीय मदद देने के लिए समर्पित है जैसे इनपुट को आपूर्ति, उत्पादन, वितरण, थोक विक्री, प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग। आधुनिक कृषि में इनपुट का इस्तेमाल बढ़ गया है खासकर बीजों, उर्वरकों, सिंचाई जल मशीनरी आदि का जिसके कारण कृषि ऋण की मांग में वृद्धि हुई है।

कृषि क्षेत्र में वित्त पोषण किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। किंतु किसानों के पास

पर्याप्त पैसा नहीं होता इसलिए उन्हें वित्तीय मदद की जरूरत पड़ती है। अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों तथा उचित दरों पर, समय पर कर्ज सुविधा के अभाव में बहुत से किसान उन्नत बीज व उर्वरक अथवा बेहतर पद्धति या तकनीक का लाभ नहीं ले पाते।

ऐसी स्थिति में कृषि क्षेत्र को सेवाएं देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) की भूमिका अत्यंत अहम हो जाती है। किसानों को वित्तीय प्रणाली में लाकर ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां देश में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को तीव्र कर रही हैं। पिछले बजटों में हमने देखा की सरकार ने नाबाई जैसे संस्थानों में सस्ते कर्ज (क्रेडिट पूल) को उपलब्ध कराया है जिन्होंने आगे जाकर ऐग्री प्रोसेसिंग एवं ऐग्री इफ़ास्ट्रक्चर को

फाइनेंसिंग को है लेकिन हमने अभी तक यह नहीं देखा की वैसा ही सस्ता क्रेडिट पूल कृषि- NBFCs को भी उपलब्ध कराया गया हो। कृषि- NBFCs छोटे किसानों को फायनेंस तक पहुंच प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती हैं, इसलिए अगर कृषि- NBFCs को भी नाबाई की ही तरह सस्ते कर्ज देकर सक्षम बनाया जाए तो भेदा मानना है की किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में इसके दीर्घकालिक सकारात्मक परिणाम होंगे और कृषि-वृद्धि का समावेशी वातावरण तैयार होगा। इसके अलावा यदि सरकार कृषि- NBFCs सेक्टर को रियायत देना शुरू करेगी तो इससे न सिर्फ यह क्षेत्र प्रगति करेगा बल्कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने का सरकार का ध्येय भी पूरा होगा।

वेअरहाउसिंग सेक्टर में अप्रत्यक्ष करों को तर्क संगत बनाया जाए

नई दिल्ली, (वीआ)। ऐग्री वेअरहाउसिंग इंडस्ट्री बहुत लंबे समय से यह मांग करती आ रही है की अप्रत्यक्ष करों को तर्क संगत बनाया जाए। ऐग्री लॉजिस्टिक्स एवं वेअरहाउसिंग के संगठित क्षेत्र में काम करने वाली कोई कंपनी जब फसल के लिए



ऐग्री इनपुट सेवाएं देती है तो वह वेअरहाउस को लीज पर लेती है और उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। इनवेअरहाउसों को लीज को कमर्शियल लीज के तहत रखा जाता है, इस कारण इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। दूसरी तरफ आउटपुट सेवाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगता। इस तरह 18 प्रतिशत जीएसटी से इन कंपनियों को लागत बढ़ जाती है जिसका बोझ ग्राहकों को उठाना पड़ता है। इस वजह से अक्सर संगठित क्षेत्र को कारोबार को हानि होती

है क्योंकि ग्राहक असंगठित क्षेत्र को ओर चले जाते हैं क्योंकि वहां अक्सर जीएसटी नहीं लगाया जाता। पिछले लगातार तीन बजटों से हम यही मांग करते आ रहे हैं कीऐसी लीज नीति बनाई जाए जिसके अंतरगत उन कमर्शियल वेअरहाउसिस को

जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए जिसका इस्तेमाल ऐग्री इनपुट रखने के लिए होता है।

ऐग्री फायनेंस प्रामोण वित्तपोषण का उपवर्ग है जो खेतीबाड़ी की गतिविधियों को वित्तीय मदद देने के लिए समर्पित है जैसे इनपुट की आपूर्ति, उत्पादन, वितरण, थोक बिना, प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग। आधुनिक कृषि में इनपुट काइस्तेमाल बढ़ गया है खासकर बीजों, उर्वरकों, सिंचाई जल व मशीनरी आदि का जिसके कारण कृषि ऋण की मांगमें वृद्धि हुई है।

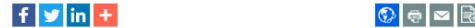
Online Coverage

Apply MSME Loan Online



Agri-warehousing cos seek GST waiver ahead of Union Budget

Press Trust of India | Kolkata
Last Updated at July 2, 2019 17:00 IST



Make Attackers Visible
Stop Attackers by Removing Security Silos & Stitching Together Network, Endpoint & Cloud. **OPEN**

ALSO READ

Govt to celebrate 2nd anniversary of GST on July 1

CAIT for lowering GST rates on auto parts, aluminium utensils

Cut in GST rate on footwear to promote growth, exports: CLE Chairman to govt

CAIT releases White Paper on GST, asks FM to lower rates

Comic book on GST

Ad Auto Elliott Wave Software WaveBasis Automatic wave counts, advanced professional charting. Easily find trade setups.

Days ahead of the Union Budget, agri-warehousing companies have sought waiver of the 18 per cent GST imposed on such services to boost the farming community.

"The Centre should relook at the GST on agri-warehousing services. It is raising the cost of farmers. I think the government should waive the GST on this sector," said Paran Dass, Transportation Director of Japanese warehousing major Kawasaki Rikuso.

The waiver will encourage farmers to store their produce and prevent distress sale, Dass told PTI.

KRT has set up a solar agri-warehouse in the state, which is used by the West Bengal Agriculture Department.

Sohan Lal Commodity Management Group CEO Sandeep Sabharwal said the GST waiver is a long-standing demand of the agri-warehousing industry.

"The leases of these warehouses are treated as commercial ones, and has an 18 per cent GST implication. On the contrary, output services are devoid of any GST and eventually, the customers' cost increases," he said.

This often leads to loss of business for the organised sector, as consumers prefer unorganised players who often do not pay GST, he said.

Finance Minister Nirmala Sitharaman will unveil the full budget for the fiscal 2019-20 on July 5.

(This story has not been edited by Business Standard staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

XAG Pseries Agricultural Drone

XAG Co., Ltd
XAG P Series UAS can spray liquid onto every needing crop with uniformity and precision.

OPEN

LATEST NEWS

IN THIS SECTION

ALL



US senators seek info from Trump govt on satellite sales to Chinese firm



Centre slams UP govt's move to include 17 OBC communities in SC list



Emirates launches world's shortest A380 flight between Dubai and Muscat



Paytm expects to achieve 2 billion transactions by end of 2019

Advertisement

ads by media.net

TOP SUPPLY CHAIN SOFTWARE

SUPPLY CHAIN LOGISTICS

More >

MOST POPULAR

READ **SHARE** **COMMENTED**



Ola Electric gets \$250 mn from SoftBank, becomes India's newest unicorn



Cash-starved DHFL likely to get fresh line of

Portal- financialexpress.com

Link - <https://www.financialexpress.com/budget/budget-2019-agri-warehousing-companies-seek-gst-waiver-ahead-of-union-budget/1626278/>

Budget 2019: Agri-warehousing companies seek GST waiver ahead of Union Budget

By: PTI | Published: July 2, 2019 6:34:08 PM

Budget 2019-20: Days ahead of the Union Budget, agri-warehousing companies have sought waiver of the 18 per cent GST imposed on such services to boost the farming community. "The Centre should relook at the GST on agri-warehousing services."



Budget 2019 India: Finance Minister Nirmala Sitharaman will unveil the full budget for the fiscal 2019-20 on July 5.

1 Crore Cover
@ ₹563/month*

Calculate Premium

UPI 10-040002031 *Classification: Non-Financial/Insurance, Term/Other Term Insurance/Plan / ADR. YOUVAIDCONCEPTS

Advertisement

DELL

Learn more >

Windows 10

Windows 10 Pro means business. > Roll o

STOCK MARKET

NSE BSE AS

NIFTY: 11913.60 +3.30

1d 1w 1m 3m 6m

09:00 10:00 11:00

Union Budget 2019 India: Days ahead of the Union Budget, agri-warehousing companies have sought waiver of the 18 per cent GST imposed on such services to boost the farming community. "The Centre should relook at the GST on agri-warehousing services. It is raising the cost of farmers. I think the government should waive the GST on this sector," said Paran Dass, Transportation Director of Japanese warehousing major Kawasaki Rikuso.

The waiver will encourage farmers to store their produce and prevent distress sale, Dass told PTI. KRT has set up a solar agri-warehouse in the state, which is used by the West Bengal Agriculture Department. Sohan Lal Commodity Management Group CEO Sandeep Sabharwal said the GST waiver is a long-standing demand of the agri-warehousing industry.

Ad closed by Google

"The leases of these warehouses are treated as commercial ones, and has an 18 per cent GST implication. On the contrary, output services are devoid of any GST and eventually, the customers' cost increases," he said. This often leads to loss of business for the organised sector, as consumers prefer unorganised players who often do not pay GST, he said.

Finance Minister Nirmala Sitharaman will unveil the full budget for the fiscal 2019-20 on July 5.

VIEW ALL MARKET DATA

Advertisement

MAX LIFE

98.74%^A
Claims Paid Percentage

#BharoseKaNumber

max life term insurance

Get 1Cr. Cover @ ₹563/month*

98.74%
Claims Paid Percentage

#BharoseKaNumber

max life term insurance

Get 1Cr. Cover @ ₹563/month*

Portal- www.livemint.com

Link - <https://www.livemint.com/budget/expectations/agri-warehousing-companies-seek-gst-waiver-ahead-of-union-budget-1562067670089.html>

live**mint**



Consumers prefer unorganised players who often do not pay GST (Ramesh Pathania/Mint)

Agri-warehousing companies seek GST waiver ahead of Union Budget

1 min read . Updated: 02 Jul 2019, 05:17 PM IST
PTI

- Sohan Lal Commodity Management Group CEO Sandeep Sabharwal said the GST waiver is a long-standing demand of the agri-warehousing industry
- The waiver will encourage farmers to store their produce and prevent distress sale, Paran Dass said

Topics

Agriculture | Union budget

KOLKATA: Days ahead of the Union Budget, agri-warehousing companies have sought waiver of the 18% GST imposed on such services to boost the farming community.

‘The Centre should relook at the GST on agri-warehousing services. It is raising the cost of farmers. I think the government should waive the GST on this sector,’ said Paran Dass, Transportation Director of Japanese warehousing major Kawasaki Rikuso.

The waiver will encourage farmers to store their produce and prevent distress sale, Dass told PTI.

KRT has set up a solar agri-warehouse in the state, which is used by the West Bengal Agriculture Department.

Sohan Lal Commodity Management Group CEO Sandeep Sabharwal said the GST waiver is a long-standing demand of the agri-warehousing industry.

‘The leases of these warehouses are treated as commercial ones, and has an 18 per cent GST implication. On the contrary, output services are devoid of any GST and eventually, the customers’ cost increases,’ he said.

This often leads to loss of business for the organised sector, as consumers prefer unorganised players who often do not pay GST, he said.

Finance Minister Nirmala Sitharaman will unveil the full budget for the fiscal 2019-20 on July 5.

This story has been published from a wire agency feed without modifications to the text. Only the headline has been changed.

Portal- www.newindianexpress.com

Link - <http://www.newindianexpress.com/business/2019/jul/02/agri-warehousing-companies-see-gst-waiver-ahead-of-union-budget-1998426.html>

 THE NEW
INDIAN EXPRESS

WORLD CUP NATION WORLD STATES CITIES BUSINESS SPORT GOOD NEWS MOVIES

Home > Business

Agri-warehousing companies seek GST waiver ahead of Union Budget

KRT has set up a solar agri-warehouse in the state, which is used by the West Bengal Agriculture Department.



Published: 02nd July 2019 05:15 PM | Last Updated: 02nd July 2019 05:15 PM |  | A+ A A-



For representational purposes

By PTI

KOLKATA: Days ahead of the Union Budget, agri-warehousing companies have sought waiver of the 18 per cent GST imposed on such services to boost the farming community.

KOLKATA: Days ahead of the Union Budget, agri-warehousing companies have sought waiver of the 18 per cent GST imposed on such services to boost the farming community.

"The Centre should relook at the GST on agri-warehousing services. It is raising the cost of farmers. I think the government should waive the GST on this sector," said Paran Dass, Transportation Director of Japanese warehousing major Kawasaki Rikuso.

The waiver will encourage farmers to store their produce and prevent distress sale, Dass told PTI.

KRT has set up a solar agri-warehouse in the state, which is used by the West Bengal Agriculture Department.

Sohan Lal Commodity Management Group CEO Sandeep Sabharwal said the GST waiver is a long-standing demand of the agri-warehousing industry.

"The leases of these warehouses are treated as commercial ones, and has an 18 per cent GST implication. On the contrary, output services are devoid of any GST and eventually, the customers' cost increases," he said.

This often leads to loss of business for the organised sector, as consumers prefer unorganised players who often do not pay GST, he said.

Finance Minister Nirmala Sitharaman will unveil the full budget for the fiscal 2019-20 on July 5.

Portal- www.newsnation.in

Link - <https://www.newsnation.in/business-news/budget-2019/agri-warehousing-companies-look-for-gst-waiver-ahead-of-union-budget-article-229445.html>

NEWS NATION  **Secure Your Wife & Child's Future**
Buy ₹ 1 Crore Term Insurance @ just ₹490 p.m* Check Premium

Home | LIVE TV | Latest News | World Cup 2019 | India | World | Entertainment | Education | Elections 2019 | Results | Videos | Photos | f

BREAKING 2 killed in firing at Pakistan's Lahore Airport, police arrests suspect - [Read More](#)

Participate in News Nation World Cup Quiz
Win an autographed Cricket kit by S Sreesanth

You are at: Home >> Business News >> Budget 2019 >> Agri-warehousing companies seek GST waiver ahead of Union Budget

Agri-warehousing companies seek GST waiver ahead of Union Budget

Days ahead of the Union Budget, agri-warehousing companies have sought waiver of the 18 per cent GST imposed on such services to boost the farming community.

Kolkata, PTI | Updated: 03 July 2019, 08:01 AM



	1-Jun	1-Jul	1-Aug	1-Sep	1-Oct	1-Nov
	1,307.85	1,240.64	1,235.42	939.09	1,300.67	843.29
	0.00	698.18	0.00	0.00	40.07	0.00
	15.80	78.42	38.16	15.62	256.67	25.46
	12.03	1,485.22	6,062.23	447.24	16,048.05	349.55
	0.00	677.87	503.91	1,094.97	5,620.31	2,560.60
	0.00	0.00	310.01	3,142.38	9,779.24	14,693.66
	0.00	0.00	670.64	1,259.50	4,294.85	7,473.24
	0.00	0.00	39,386.87	17,848.02	34,414.47	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	19,577.90	11,799.74	14,874.16	33,010.21
	0.00	0.00	1,335.55	21.76	865.15	348.10
	0.00	0.00	0.00	0.00	12,032.74	24,740.68
	0.00	0.00	0.00	0.00	4,387.73	18,444.80
	0.00	0.00	0.00	701.60	4,796.53	502.91
	0.00	0.00	0.00	2,144.68	2,000.27	1,727.45
	0.00	0.00	0.00	0.857,02	0.00	82.02
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	2.93	0.00	4,829.68
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.19	15,23
	0.00	0.00	0.00	131.43	160.07	0.00
	0.00	0.00	0.00	101,087.81	143,638.64	0.00

Finance Minister Nirmala Sitharaman will unveil the full budget for the fiscal 2019-20 on July 5. (File Photo)



Commercial NFT Farms High return investments on Hydroponic Commercial Farms

Days ahead of the Union Budget, agri-warehousing companies have sought waiver of the 18 per cent GST imposed on such services to boost the farming community. "The Centre should relook at the GST on agri-warehousing services. It is raising the cost of farmers. I think the government should waive the GST on this sector," said Paran Dass, Transportation Director of Japanese warehousing major Kawasaki Rikuso.

The waiver will encourage farmers to store their produce and prevent distress sale, Dass told PTI.

KRT has set up a solar agri-warehouse in the state, which is used by the West Bengal Agriculture Department.

Sohan Lal Commodity Management Group CEO Sandeep Sabharwal said the GST waiver is a long-standing demand of the agri-warehousing industry.

"The leases of these warehouses are treated as commercial ones, and has an 18 per cent GST implication. On the contrary, output services are devoid of any GST and eventually, the customers' cost increases," he said.

This often leads to loss of business for the organised sector, as consumers prefer unorganised players who often do not pay GST, he said.

Finance Minister Nirmala Sitharaman will unveil the full budget for the fiscal 2019-20 on July 5.

BIZ-AGRI WAREHOUSING

PTI | July 02, 2019 17:02 IST

Agri-warehousing cos seek GST waiver ahead of Union Budget
Kolkata, Jul 2 (PTI) Days ahead of the Union Budget, agri-warehousing companies have sought waiver of the 18 per cent GST imposed on such services to boost the farming community.

"The Centre should relook at the GST on agri-warehousing services. It is raising the cost of farmers. I think the government should waive the GST on this sector," said Paran Dass, Transportation Director of Japanese warehousing major Kawasaki Rikuso.

The waiver will encourage farmers to store their produce and prevent distress sale, Dass told PTI.

KRT has set up a solar agri-warehouse in the state, which is used by the West Bengal Agriculture Department.

Sohan Lal Commodity Management Group CEO Sandeep Sabharwal said the GST waiver is a long-standing demand of the agri-warehousing industry.

"The leases of these warehouses are treated as commercial ones, and has an 18 per cent GST implication. On the contrary, output services are devoid of any GST and eventually, the customers' cost increases," he said.

This often leads to loss of business for the organised sector, as consumers prefer unorganised players who often do not pay GST, he said.

Finance Minister Nirmala Sitharaman will unveil the full budget for the fiscal 2019-20 on July 5. PTI BSM BDC
RBT RBT

(This story has not been edited by THE WEEK and is auto-generated from a PTI feed.)

Portal- www.devdiscourse.com

Link - <https://www.devdiscourse.com/article/business/583035-agri-warehousing-cos-seek-gst-waiver-ahead-of-union-budget>

<https://www.devdiscourse.com/article/business/583035-agri-warehousing-cos-seek-gst-waiver-ahead-of-union-budget>

Devdiscourse
Discourse on Development

ABOUT CAREER ADVERTISEMENT TEAM PARTNERSHIP

EDITION HOME NEWS & ANALYSIS RESEARCH LIVE DISCOURSE BLOG / OPINION SUBMIT PRESS RELEASE

Agro-Forestry Art & Culture Technology Economy & Business Education Energy & Extractives Politics Law & Governance Health Science & Environment



Home > News > Business > Article

Agri-warehousing cos seek GST waiver ahead of Union Budget

PTI Kolkata | Updated: 02-07-2019 17:06 IST | Created: 02-07-2019 17:03 IST



Days ahead of the Union Budget, agri-warehousing companies have sought a waiver of the 18 per cent GST imposed on such services to boost the farming community. "The Centre should relook at the GST on agri-warehousing services. It is raising the cost of farmers. I think the government should waive the GST on this sector," said Paran Dass, Transportation Director of Japanese warehousing major Kawasaki Rikuso.

The waiver will encourage farmers to store their produce and prevent distress sale, Dass told PTI. KRT has set up a solar agri-warehouse in the state, which is used by the West Bengal Agriculture Department.

Sohan Lal Commodity Management Group CEO Sandeep Sabharwal said the GST waiver is a long-standing demand of the agri-warehousing industry. "The leases of these warehouses are treated as commercial ones and has an 18 per cent GST implication. On the contrary, output services are devoid of any GST and eventually, the customers' cost increases," he said.

This often leads to loss of business for the organised sector, as consumers prefer unorganised players who often do not pay GST, he said. Finance Minister Nirmala Sitharaman will unveil the full budget for fiscal 2019-20 on July 5.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

Portal- www.timesnownews.com

Link -<https://www.timesnownews.com/business-economy/budget/article/agri-warehousing-companies-seek-gst-waiver-ahead-of-union-budget/447272>

/business-economy/budget/article/agri-warehousing-companies-seek-gst-waiver-ahead-of-union-budget/447272

27% Magazine Readers in India belong to NCCS A

Want to Advertise in Magazines?

Check Rates



41st match - Riverside Ground, Chester-le-Street ENG vs NIZ WEDNESDAY 3RD JULY 2019 Match scheduled to begin at 3:00 PM IST	42nd match - Headingley, Leeds AFG vs WI THURSDAY 4TH JULY 2019 Match scheduled to begin at 3:00 PM IST	BAN
--	--	-----

Home > Business > Budget 2019

Agri-warehousing companies seek GST waiver ahead of Union Budget

Budget 2019

Updated Jul 02, 2019 | 17:50 IST | PTI



Sohan Lal Commodity Management Group CEO Sandeep Sabharwal said the GST waiver is a long-standing demand of the agri-warehousing industry.



(Representational image) | Photo Credit: Thinkstock

Kolkata: Days ahead of the Union Budget, agri-warehousing companies have sought waiver of the 18 per cent GST imposed on such services to boost the farming community. "The Centre should relook at the GST on agri-warehousing services. It is raising the cost of farmers. I think the government should waive the GST on this sector," said Paran Dass, Transportation Director of Japanese warehousing major Kawasaki Rikuso.

The waiver will encourage farmers to store their produce and prevent distress sale, Dass told PTI. KRT has set up a solar agri-warehouse in the state, which is used by the West Bengal Agriculture Department.

Sohan Lal Commodity Management Group CEO Sandeep Sabharwal said the GST waiver is a long-standing demand

of the agri-warehousing industry.

"The leases of these warehouses are treated as commercial ones, and has an 18 per cent GST implication. On the contrary, output services are devoid of any GST and eventually, the customers' cost increases," he said.

This often leads to loss of business for the organised sector, as consumers prefer unorganised players who often do not pay GST, he said. Finance Minister Nirmala Sitharaman will unveil the full budget for the fiscal 2019-20 on July 5.

Visit Times Now for the latest Budget 2019 news and also get all news on Business, Income Tax, GST on a single tap.

0 Comments

Sort by Newest

icicprulife.com

Pay Premium for just 5 Years & Get Life Cover till 85 Years.

CHECK PREMIUM

T&C apply W/II/3689/2018-19

JUST IN MOST READ VIDEOS

Modi praises Chirag Paswan, asks MPs to follow his example

Bengal: School segregates students to stop 'harassment'

Malaika Arora shares love post for beau Arjun Kapoor

Health benefits of retail therapy

Mumbai rains cripple train services - Complete schedule here

हिंदी मराठी
தமிழ்

Portal- www.dailypioneer.com

Link -<https://www.dailypioneer.com/2019/business/agri-warehousing-cos-seek-gst-waiver-ahead-of-union-budget.html>

<https://www.dailypioneer.com/2019/business/agri-warehousing-cos-seek-gst-waiver-ahead-of-union-budget.html>



HOME DELHI INDIA BUSINESS WORLD SPORTS OPINION ANALYSIS STATE EDITIONS E-PAPER
FEATURES Vivacity Health Travel Show Time Backpack Special Avenues AGENDA - THE SUM

HOME > BUSINESS

Agri-warehousing cos seek GST waiver ahead of Union Budget

Wednesday, 03 July 2019 | PTI | Kolkata



SHARE



Days ahead of the Union Budget, agri-warehousing companies have sought waiver of the 18 per cent GST imposed on such services to boost the farming community.

“The Centre should relook at the GST on agri- warehousing services. It is raising the cost of farmers. I think the government should waive the GST on this sector,” said Paran Dass, Transportation Director of Japanese warehousing major Kawasaki Rikuso.

The waiver will encourage farmers to store their produce and prevent distress sale, Dass told PTI.



KRT has set up a solar agri-warehouse in the state, which is used by the West Bengal Agriculture Department.



Sohan Lal Commodity Management Group CEO Sandeep Sabharwal said the GST waiver is a long-standing demand of the agri-warehousing industry.



“The leases of these warehouses are treated as commercial ones, and has an 18 per cent GST implication. On the contrary, output services are devoid of any GST and eventually, the customers' cost increases,” he said.

This often leads to loss of business for the organised sector, as consumers prefer unorganised players who often do not pay GST, he said.



News Now

Home / News Now /

What are the expectations of Agri Sector from Modi 2.0 government's first Budget?

Commodity Online | July 02 2019
UPDATED 16:03:37 IST

MAIL | PRINT A+ A-

Ad closed by Google

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Tweet Email Share



In this article Mr. Sandeep Sabharwal, Group CEO, Sohan Lal Commodity Management Pvt. Ltd, has shared his view on pre-budget expectations of agri-warehousing, agri-logistics, and agri NBFCs.

One of the long outstanding demands of the Agri warehousing industry has been the rationalisation of indirect taxes. When an organised player operating in the Agri logistics and warehousing sector segment goes out to give agri-input services against a crop, it hires warehouses on lease and implements technology on it.

The leases of these warehouses are treated as a commercial lease and it has an 18% GST implication. On the contrary output, services are devoid of any GST. So the 18 percent GST actually becomes a cost on my balance sheet and increases my costing which I have to pass on to my customers.

This often leads to loss of Business for the organized sector as customer's moves on to the unorganized players who often do not be charged the GST. So one of the outstanding demands for the successive last three budgets has been that there has to carve out to such leases to such commercial places which are actually used as agri-input place. So that's one important point I would like to make.

Agri Credit

Agricultural finance is a subset of rural finance dedicated to financing agricultural related activities such as input supply, production, distribution, wholesale, processing, and marketing. The modern agriculture has increased the use of inputs especially for seed, fertilizers, irrigational water, machinery and implements, which has increased demand for agricultural credit.

Finance in agriculture acts as a key to farmers. But farmers' money is always inadequate and he needs outside finance or credit. Because of inadequate financial resources and the absence of timely credit facilities at reasonable rates, many of the farmers, are unable to go in for improved seeds and manures or to introduce better methods or techniques.

In the given situation, the role of agricultural NBFC's becomes extremely important. By bringing farmers to the financial system these NBFC(Non-Banking Financial Company) accelerates the process of financial inclusion in the country. We have seen in successive budgets that the government has made cheaper credit pools available to institutions like NABARD who have further gone ahead and given those financing activity to agri-processing and agri-infrastructure but we have not such seen such cheaper pool of credit available to Agri-NBFCs.

Agri-NBFCs plays an important role in providing access to Finance for smallholder farmers and therefore if cheaper credit is made available to the Agri NBFC's just like the way it is given to NABARD, I think it is going to go a long way in doubling farmer income also in making inclusive agri-growth environment. Also if the government starts offering SOP's to the Agri-NBFC sector, it will go a long way in helping the sector to flourish and will also help in fulfilling the government vision of doubling farmers' income.

Initiatives like e-NAM

Initiatives like e-NAM which talks about one mandi or one environment and one Agri credit market as well as one output market are good initiatives but they need to be backed by good physical infrastructure. Agri companies which can provide end to end physical gambit of the agri-value chain should be encouraged for participating in this initiative.

- ▶ Rising stocks and uncertain demand cloud global Cotton outlook
- ▶ Indonesia Palm Oil output rises to 4.6 MT in May: survey
- ▶ India's Coffee exports decline 6% in June quarter
- ▶ ONGC discovers 230 MT of Oil reserves: Petroleum Minister
- ▶ Delayed monsoon slows sowing of kharif crops

Portal- indianshowbiz

Link - <http://www.indianshowbiz.com/?p=188485>

The screenshot shows the top section of the IndianShowBiz.com website. At the top left is the logo "IndianShowBiz.com" in white on a dark background. To the right are social media icons for Twitter and Facebook. Below the logo is a navigation menu with the following items: Home, Entertainment, Fashion, Events, Life Style, Social, Sports, and Business. A large purple banner below the menu features the "ISB IndianShowBiz.com" logo and the tagline "One-stop Website on Indian Entertainment, Events & Showbusiness" next to a film strip graphic. Below the banner, there is a search bar and a "No comments" button. The main article title "Sohan Lal Commodity Management Pvt. Ltd." is displayed in large, bold black text. Below the title are social sharing icons and a byline: "By K Ashwin Mobile: 09920183006 Email: indianshowbusiness@gmail.com". To the right of the article is a "Social Media" section with Twitter and Facebook icons, and a "Publisher's Contact Info" section with the following details: "Publisher & Editor : K Ashwin, Mobile : +91 9920183006, Email : indianshowbusiness@gmail.com".



Mr Sandeep Sabharwal, CEO, SLCM Group

RATIONALISATION OF INDIRECT TAXES ON WAREHOUSING SECTOR

Archives

- > July 2019 (36)
- > June 2019 (616)
- > May 2019 (404)
- > April 2019 (300)
- > March 2019 (300)
- > February 2019 (3)
- > January 2019 (32)
- > December 2018 (
- > November 2018 (
- > October 2018 (34
- > September 2018
- > August 2018 (356
- > July 2018 (400)
- > June 2018 (402)
- > May 2018 (402)
- > April 2018 (400)
- > March 2018 (400
- > February 2018 (4
- > January 2018 (40
- > December 2017 (

One of the long outstanding demands of the agri warehousing industry has been the rationalization of indirect taxes. When an organised player operating in the agri logistics and warehousing sector segment goes out to give agri-input services against a crop, it hires warehouses on lease and implement technology on it. The leases of these warehouses are treated as a commercial lease and it has an 18% GST implication. On the contrary output services are devoid of any GST. So the 18% GST actually becomes a cost on my balance sheet and increases my costing which I have to pass on to my customers .

This often leads to loss of Business for the organized sector as customer's moves on to the unorganized players who often does not be charge the GST. So one of the outstanding demands for the successive last three budgets have been that there has to carve out to such leases to such commercial places which are actually used as agri-input place. So that's one important point I would like to make.

AGRI CREDIT

Agricultural finance is a subset of rural finance dedicated to financing agricultural related activities such as input supply, production, distribution, wholesale, processing and marketing. The modern agriculture has increased the use of inputs especially for seed, fertilizers, irrigational water, machineries and implements, which has increased demand for agricultural credit.

Finance in agriculture act as a key to farmers. But farmers' money is always inadequate and he needs outside finance or credit. Because of inadequate financial resources and absence of timely credit facilities at reasonable rates, many of the farmers, are unable to go in for improved seeds and manures or to introduce better methods or techniques.

In the given situation, the role of agricultural NBFC's becomes extremely important. By bringing farmers to the financial system these NBFC(Non Banking Financial Company)'s accelerates the process of financial inclusion in the country. We have seen in successive budgets that government has made cheaper credit pools available to institutions like NABARD who have further gone ahead and given those financing activity to agri-processing and agri-infrastructure but we have not such seen such cheaper pool of credit available to agri-NBFCs.

Agri-NBFCs plays an important role in providing access to Finance for smallholder farmers and therefore if cheaper credit is made available to the Agri NBFC's just like the way it is given to NABARD, I think it is going to go a long way in doubling farmer income also in making inclusive agri-growth environment. Also if the govt. starts offering SOP's to the Agri-NBFC sector , it will go a long way in helping the sector to flourish and will also help in fulfilling the government vision of doubling farmers' income.

Initiatives like e-NAM

Initiatives like e-NAM which talks about one mandi or one environment and one Agri credit market as well as one output market are good initiatives but they need to be backed by good physical infrastructure. Agri companies which can provide end to end physical gambit of agri-value chain should be encouraged for participating in this initiative.

- > October 2017 (652)
- > September 2017 (471)
- > August 2017 (613)
- > July 2017 (611)
- > June 2017 (623)
- > May 2017 (620)
- > April 2017 (617)
- > March 2017 (608)
- > February 2017 (623)
- > January 2017 (623)
- > December 2016 (630)
- > November 2016 (614)
- > October 2016 (623)
- > September 2016 (625)
- > August 2016 (650)
- > July 2016 (622)
- > June 2016 (621)
- > May 2016 (298)
- > April 2016 (602)

- > March 2016 (627)
- > February 2016 (621)
- > January 2016 (622)
- > December 2015 (725)
- > November 2015 (712)
- > October 2015 (704)
- > September 2015 (602)
- > August 2015 (729)
- > July 2015 (631)
- > June 2015 (553)
- > May 2015 (493)
- > April 2015 (735)
- > March 2015 (784)
- > February 2015 (754)
- > January 2015 (710)
- > December 2014 (696)

Portal- www.deccanherald.com

Link - <https://www.deccanherald.com/business/budget-2019/rationalisation-of-indirect-taxes-on-warehouse-sector-744484.html>

Rationalisation of indirect taxes on warehouse sector

DH Web Desk, Bengaluru, JUL 03 2019, 12:56PM IST | UPDATED: JUL 03 2019, 14:15PM IST



pcs/click?xai=AKAOjsudmqUGCAEYryqSKbx_YanJ8WPWRFN... EO, Sohan Lal Commodity Management Pvt. Ltd.

DH P

By Mr Sandeep Sabharwal

One of the long outstanding demands of the Agri warehousing industry has been the rationalization of indirect taxes. When an organised player operating in the Agri logistics and warehousing sector segment goes out to give agri-input services against a crop, it hires warehouses on lease and implements technology on it. The leases of these warehouses are treated as a commercial lease and it has an 18% GST implication. On the contrary output, services are devoid of any GST. So the 18% GST actually becomes a cost on my balance sheet and increases my costing which I have to pass on to my customers.

This often leads to loss of Business for the organized sector as customer's moves on to the unorganized players who often do not be charged the GST. So one of the outstanding demands for the successive last three budgets has been that there has to carve out to such leases to such commercial places which are actually used as agri-input place. So that's one important point I would like to make.

AGRI CREDIT

Agricultural finance is a subset of rural finance dedicated to financing agricultural-related activities such as input supply, production, distribution, wholesale, processing and marketing. The modern agriculture has increased the use of inputs especially for seed, fertilizers, irrigational water, machinery and implements, which has increased demand for agricultural credit.

Finance in agriculture act as a key to farmers. But farmers' money is always inadequate and he needs outside finance or credit. Because of inadequate financial resources and absence of timely credit facilities at reasonable rates, many of the farmers, are unable to go in for improved seeds and manures or to introduce better methods or techniques.

In the given situation, the role of agricultural NBFC's becomes extremely important. By bringing farmers to the financial system these NBFC(Non-Banking Financial Company) accelerates the process of financial

inclusion in the country. We have seen in successive budgets that government has made cheaper credit pools available to institutions like NABARD who have further gone ahead and given those financing activity to agri-processing and agri-infrastructure but we have not such seen such cheaper pool of credit available to Agri-NBFCs.

Agri-NBFCs plays an important role in providing access to finance for smallholder farmers and therefore if cheaper credit is made available to the Agri NBFC's just like the way it is given to NABARD, I think it is going to go a long way in doubling farmer income also in making inclusive agri-growth environment.

Also if the govt. starts offering SOP's to the Agri-NBFC sector, it will go a long way in helping the sector to flourish and will also help in fulfilling the government vision of doubling farmers' income.

Initiatives like e-NAM

Initiatives like e-NAM which talks about one mandi or one environment and one Agri credit market as well as one output market are good initiatives but they need to be backed by good physical infrastructure. Agri companies which can provide end to end physical gambit of the agri-value chain should be encouraged for participating in this initiative.

The author is Group CEO at Sohan Lal Commodity Management Pvt. Ltd.

Portal- www.india.com

Link - <https://www.india.com/business/union-budget-2019-agri-warehousing-companies-seek-gst-waiver-to-boost-farming-community-3706572/>

Union Budget 2019: Agri-warehousing Companies Seek GST Waiver to Boost Farming Community

The agri-warehousing companies have sought a waiver of the 18 per cent Goods and Services Tax imposed on their services in order to boost the farming community.

Published: July 3, 2019 3:03 PM IST

By India.com Business Desk | Edited by Kanimozhi Sudhakar

[Share](#) [Tweet](#) [Comments](#)



[Representational Image]

Kolkata: Agri-warehousing companies have sought a waiver of 18 per cent Goods and Services Tax (GST) imposed on their services days ahead of the [Union Budget](#) for this year. The expected waiver would provide a fillip to the farming community, they say.

Speaking in favour of the waiver, Transportation Director of Japanese warehousing major Kawasaki Rikuso Paran Dass said, "The Centre should relook at the GST on agri-warehousing services. It is raising the cost of farmers. I think the government should waive the GST in this sector." Dass added that the waiver of the 18 per cent GST will motivate farmers to store their produce and prevent distress sale. Besides, Kawasaki-Rikuso Transportation Co., Ltd. (KRT) has set up a solar agri-warehouse in West Bengal, which is currently being used by the state's Agriculture Department.

Meanwhile, Sandeep Sabharwal, the CEO of global post-harvest agri-logistics group Sohan Lal Commodity Management Group said that the GST waiver is a long-standing demand of the agri-warehousing industry. A report quoted Sabharwal as saying, "The leases of these warehouses are treated as commercial ones and has an 18 per cent GST implication. On the contrary, output services are devoid of any GST and eventually, the customers' cost increases." This often leads to loss of business for the organised sector, as consumers prefer unorganised players who often do not pay GST, he added.

Ad closed by Google

Finance Minister Nirmala Sitharaman will unveil the full budget for fiscal 2019-20 on July 5. Her budget team comprises Minister of State for Finance Anurag Singh Thakur and Chief Economic Advisor Krishnamurthy Subramanian. The official team is led by Finance Secretary Subhash Chandra Garg, Expenditure Secretary Girish Chandra Murmu, Revenue Secretary Ajay Bhushan Pandey, DIPAM Secretary Atanu

Chakraborty, and Financial Services Secretary Rajiv Kumar.

In her budget, the 59-year-old JNU alumna will have to address slowing economy, financial sector troubles like rising NPAs and liquidity crisis in NBFCs, job creation, private investments, exports revival, agrarian crisis and raise public investment without compromising on fiscal prudence.



होम > बिजनेस

Budget Demand: कृषि भंडारण कंपनियों की बजट में जीएसटी छूट की मांग

| बिजनेस

Updated Jul 03, 2019 | 18:03 IST | भाषा



Budget: बजट को लेकर कृषि भंडारण कंपनियों ने बड़ी मांग की है। इन कंपनियों का कहना है कि इनको जीएसटी से छूट मिलनी चाहिए। यहां जानिए इनकी बड़ी मांगें।



प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे में संगठित क्षेत्र को कारोबार का नुकसान होता है। उपभोक्ता असंगठित क्षेत्र को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि वे कई बार जीएसटी नहीं चुकाते हैं।

जापान की भंडारण कंपनी कावासाकी रिकूसो के परिवहन निदेशक पारन दास ने कहा, 'केंद्र को कृषि भंडारण सेवाओं पर जीएसटी को लेकर नए सिरे से विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को इस क्षेत्र से जीएसटी समाप्त करना चाहिए।'

दास ने कहा कि इस तरह की छूट से किसान अपनी उपज का भंडारण करने को प्रोत्साहित होंगे और सस्ते दामों पर अपने उत्पाद नहीं बेचेंगे। केआरटी ने राज्य में सौर कृषि भंडारण गृह स्थापित किया है जिसका इस्तेमाल पश्चिम बंगाल के कृषि विभाग द्वारा किया जा रहा है।

बजट 2019 से जुड़ी सभी बड़ी खबरें टाइम्स नाउ हिंदी पर | इनकम टैक्स, बीमा, निवेश से जुड़ी सभी समाचार

कोलकाता: कृषि क्षेत्र की भंडारण कंपनियों ने आगामी बजट में इस तरह की सेवाओं पर लगने वाले 18 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को समाप्त करने की मांग की है। इन कंपनियों का कहना है कि इससे कृषक समुदाय को प्रोत्साहन मिलेगा।

सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट के ग्रुप सीईओ संदीप सभरवाल के मुताबिक एग्री वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री की मांग है कि अप्रत्यक्ष करों को तर्क संगत बनाया जाएगा। इन पर 18 फीसदी जीएसटी है जिससे लागत बढ़ जाती है और ग्राहकों पर भार पड़ता है।

सभरवाल के मुताबिक इसके लिए लीज नीति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कृषि एनबीएफसी को नाबाई की तरह सस्ता कर्ज देकर सक्षम बनाया जाए तो किसानों की आय दोगुनी हो सकती है।

उनके मुताबिक e-NAM जैसे कदम अच्छे हैं इनके लिए एग्री कंपनियों को

Electronic Coverage

Channel- CNBC TV 18

Link - <https://youtu.be/yxl2ujMij9I>

BUDGET

LIVE
SANDEEP
SABHARWAL
CEO
SLCM GROUP

Market At Close
Market Up For 2nd Straight Day; Sensex
& Nifty At 2-week Closing Highs

Sensex
39592.08
+0.40%

Nifty 50 Jun
11862.00
Prem 14.50

0.0005 \$ Vs EURO 0.8800 ▲ 0.0003 \$ Vs

TCofe¹ 387.2k 82.45 ▲ 2.40 | Texrall¹⁰ 198.1k 69.15

CNBC TV 18